State Agriculture Ministers Conference at Delhi on National Agriculture Policy

4426. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether in view of the deliberations at the State Agriculture Ministers' Conference held in New Delhi on 19th February, 1997 Government have since finalised the contemplated National Agriculture Policy;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the steps taken and being taken in the light thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) The Draft Agriculture Policy Resolution prepared by the Government is under finalisation keeping in view the suggestions made in State Agriculture ministers' Conference held in New Delhi on 19th February, 1997.

News-item captioned "Agriculture a neglected field, says C.I.I."

4427. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem, captioned, "Agriculture a neglected field, says C.I.I." Published in 'The Statesman', dated April 24, 1997; and

(b) if so, the steps taken/proposed to be taken to infuse technological dynamism in the agricultural sector to alleviate stagnation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) Strengthening of agricultural research and transfer of new technology to farm level are the major components of the strategy of agricultural development in the country.

261 Krishi Vigyan Kendras have been established by the Indian Council of Agriculture Research (ICAR) in 253 districts in the country with an objective of testing and transfer of agricultural technology through vocational training to farmers & farm women, on farm testing, frontline demonstrations and in-service training to extension functionaries. Besides this the ICAR has also launched an innovative project on Technology Assessment & refinement through Institution Village Linkage Programme (IVLP) in the year 1995 on Pilot basis in 42 selected centres in the country. Extension services in major States and trainig infrastructure have been strengthened with World Bank assistance under the National Agricultural Extension Project (NAEP). Information communication support for dissomination of improved farm technology is also provided through farm fairs fields days, screening of films, holding exhibitions and through print/mass media.

भारतीय जल विभाजक और कृषि प्रबंधन केन्द्र की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

4428. **श्री राघव जी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय जल विभाजक और कृषि प्रबंधन केन्द्र (इंडियन मैनेजमेंट सैंटर फार वाटरशेड एंड फार्मिंग) की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से भारतीय जल विभाजक और कृषि प्रबंधन केन्द्र (इंडियन मैनेजमेंट फार वाटरशेड एंड फार्मिंग) की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव

प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

देश में खाद्यान्न उत्पादन की दरों में अन्तर

4429. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न अंचलों में खाद्यान्न उत्पादन की दरों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न अंचलों में गेहूं, धान, दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन दरें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन दरों के बीच अंतर कम करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) खाद्यान्न उत्पादन की दर अर्थात् प्रति हैक्टेयर उत्पादकता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है जो विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई क्षमता, मृदा उर्वरता, आदानों के प्रयोग और अन्य संसाधन संबंधी सम्पन्नता पर निर्भर करता है। 1995-96 के दौरान गेहूं,चावल, दालों, मोटे अनाजों और सभी खाद्यान्नों के साथ-साथ तिलहनों की राज्य-वार उत्पादकता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। फसलों की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता करने वाले राज्य भी विवरण में इंगित किए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में इन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न फसलोन्मुखी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है अर्थात् गेहूं, चावल, तथा मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

विवरण

1995-96 के दौरान गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालों तथा सभी खाद्यान्नों तथा तिलहनों की राज्य-वार उत्पादकता

राज्य	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	दाल	सभी खाद्यान्न	तिलहन
आंध्र प्रदेश	—	2499	1152	416	1719	918
असम	1108	1354	621	534	1306	515
बिहार	2018	1374	1567	620	1465	625
गुजरात	2220	1450	925	543	1094	741
हरियाणा	3692	2222	758	972 (अ.उ.)	2537	1282
हिमाचल प्रदेश	1435	1346	2006 (अ.उ.)	340 (न्यू.उ.)	1615	—
जम्मू व कश्मीर	1461	1863	1469	520	1541	424 (न्यू.उ.)
कर्नाटक	686 (न्यू.उ)	2380	1294	474	1292	685
केरल	—	1974	—	800	1902	601
मध्य प्रदेश	1614	1104	801	604	1020	870
महाराष्ट्र	1279	1689	845	503	879	775